खुले में रखा गया खाद्यान्न

*483 **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री चतुर्भुज :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सरकार द्वारा वसूल किया गया खाद्यान्न का समूचा स्टाक ढके हुए स्टोरों में रखा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ढके हुए स्टोरों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न रखा गया है और खुले में कितना खाद्यान्न अभी भी पड़ा हुआ है ; और

(ग) खुले में पड़े खाद्यान्न के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष कितना व्यय किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). कुल सरकारी स्टाक के आकार और उपलब्ध ढके हुए गोदामों तथा संचालन क्षमता को भी ध्यान में रखकर, परिचालन की दृष्टि से ढके हुए गोदामों में वसूल किए गए खाद्यान्नों का सारा स्टाक रखना सम्भव नहीं है। विभिन्न राज्यों में पहली जुलाई, 1978 को ढके हुए गोदामों में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की कुल मात्रा 104.19 लाख मीटरी टन और खुले में 41.55 लाख मीटरी टन है। इसमें इस वर्ष वसूल की गई मात्रा और पिछले वर्ष का स्टाक शामिल है।

(ग) साधारणतया, खुले भण्डारण की प्रति मीटरी टन वार्षिक परिचालन लागत 40.90 रुपये है।

Set up of Rajasthan Canal

*485. SHRI YAGYA DATT SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan Canal set up is being spruced up;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons for laxity in the past?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Rajasthan Canal Project is being executed by the Government of Rajasthan. For this purpose, the State Government has set up the Rajasthan Canal Board for the construction of the Canal and its irrigation distribution system and also for carrying out the works for the Commanded Area Development. As the Rajasthan Canal Board, with its present set-up, is able to achieve the envisaged physical and financial outputs, there is no proposal before the Government of Rajasthan to spruce up the set-up for Rajasthan Canal Project.

(b) and (c). Do not arise.

आपात स्थिति के दौरान डी० डी० ए० द्वारा निर्मित त्रुटिपूर्ण मकान

*487 **श्री गंग भक्त सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से सहमत है कि आपात स्थिति अर्थात वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान डी० डी० ए० द्वारा बनाये गये मकान त्रुटिपूर्ण हैं और उनका निर्माण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों की त्रुटियों की जांच करने के लिए सरकार ने समिति गठित की है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में लोगों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). जी, नहीं। निर्माण के दौरान निर्माण संबंधी कोई मुख्य त्रुटि नहीं पाई गई है। तथापि, आवंटन के बाद कुछ मकानों में छोटी-छोटी त्रुटियां बताई गई थीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन त्रुटियों को समय समय पर ठीक किया गया था।